

कृषि उत्पादन

+

- \*१०. { श्री रा० स० तिवारी :  
 श्री वैकटामुखिया :  
 श्री योगेन्द्र झा :  
 श्री दी० चं० शर्मा :  
 श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :  
 श्री ब्रज राज सिंह :  
 श्री यशपाल सिंह :  
 श्री विद्याचरण शुक्ल :  
 श्री इन्द्र जे० प्लहोत्रा :  
 श्री दाजी :  
 श्री एस० एम० बनर्जी :  
 श्री न्द्रजोत गुप्त :  
 श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :  
 श्री आ० पी० सिंह :  
 श्री प्रकाश वीर शास्त्री :  
 श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :  
 श्री पी० सी० बरुआ :  
 श्री हेम राज :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने राष्ट्रीय विकास परिषद् की स्थाई समिति को एक योजना भेजी है, जिसके अनुसार कृषि उत्पादन बढ़ाया जायेगा तथा प्रत्येक राज्य के कुछ जिलों को इस कार्य के लिये चुना जायेगा ;

(ख) उत्पादन बढ़ाने के लिये उन जिलों को किस प्रकार की सहायता दी जा रही है; और

(ग) क्या सहायता राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम० सुभग सिंह) : (क) जी हाँ ।

(ख) और (ग) : पूछी हुई जानकारी का एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

१. सघन चावल उत्पादन कार्यक्रम :

(१) राज्य सरकारों से प्रार्थना की गई है कि वे एक अतिरिक्त विस्तार अधिकारी तथा पर्याप्त संख्या में ग्राम सेवकों की नियुक्ति करके विस्तार स्टाफ को सुदृढ़ करें ताकि प्रत्येक ग्राम सेवक को सघन खेती की ४००० एकड़ से अधिक भूमि की देखभाल न करनी पड़े ।

(२) यह सुझाव दिया गया है कि पौद रक्षा सम्बन्धी कार्यों के लिये उपदान की मात्रा को २५ प्रतिशत से ५० प्रतिशत तक बढ़ा दिया जाये और इस खर्च को केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें आधा आधा बांट लें ।

(३) विभिन्न क्षेत्रों में चावल तथा धान की खरीद के लिये एक उचित क्रय मूल्य निर्धारित कर दिया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसान को इस उत्पादन के लिये लाभकारी कीमत मिल सके ।

(४) राज्यों को कहा गया है कि वे चावल उत्पादन के लिये आवश्यक उपकरणों की खरीद के लिये किसानों तथा पंचायतों को २५ प्रतिशत उपदान दें ।

२. चुने हुए जिलों में ज्वार, बाजरा तथा दालों के लिये सूखी खेती और सघन उत्पादन कार्यक्रम :

- (१) यह सुझाव दिया गया है कि चावल की तरह ज्वार, बाजरे तथा दालों के लिये भी खण्डों के विस्तार स्टाफको सुदृढकिया जाय ।
- (२) इन फसलों के उत्पादन को बढ़ाने हेतु कृषि औजारों के लिये २५ प्रतिशत उपदान, विशेष रूप से स्वीकार किया गया है; यह भार पूर्ण रूप से भारत सरकार ही उठायेगी ।

उपरोक्त दोनों प्रोत्साहनों के अलावा कीटनाशियों, फुहारने तथा बुरकने के यन्त्रों और फास-फोरस पूरक उर्वरकों के लिये २५ प्रतिशत उपदान जो पहले ही तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत उपलब्ध है, से भी लाभ उठाया जा सकता है ।

३. सब्जियों की सघन उगाई :

- (१) सब्जियां उगाने के इच्छुक किसानों को सब्जियों के बीज हैं । रियायती दर पर देने का प्रस्ताव आवश्यकता के समय केन्द्रीय सरकार सब्जियों के बीजों की उपलब्धि तथा सम्भरण के लिये राज्य सरकारों को सहायता देगी । इस कार्य के लिये राज्य सरकारों को अल्पकालीन ऋण भी दिया जा रहा है ।

४. कपास तथा तिलहन :

- (१) उन्नत बीज : संकर मक्का तथा जूट की भान्ति मूंग-फली तथा तिलहन के लिये भी

उपदान मिल सकेगा और इस उपदान का भार केन्द्रीय तथा राज्य सरकार आपस में आधा आधा बाँटेंगी ।

- (२) वनस्पति रक्षा संबंधी कार्य : अब तक कीटनाशी औषधियों के फुहारने तथा बुरकने आदि के यंत्रों के विषय में लागत के ५० प्रतिशत भाग तक के लिये उपदान दिया जाता था और इस राशि को केन्द्रीय तथा राज्य सरकार आधी आधी बाँटती थी । भारत सरकार ने स्वीकार किया है कि वह भविष्य में उपदान के अपने २५ प्रतिशत भाग को दे देगी और इस बात का आग्रह न करेगी कि राज्य सरकारें भी बराबर की राशि दें ।

- (३) उर्वरक : भारत सरकार राज्य सरकारों को कपास के लिये उर्वरकों का अतिरिक्त कोटा देगी । यह कोटा उस कोटे के अलावा होगा जो कि राज्यों को पहले ही मिल रहा है ।

- (४) अल्पकालिक ऋण : किसानों द्वारा उन्नत बीजों की खरीद तथा उनके वितरण के लिये राज्य सरकारों द्वारा अल्पकालिक ऋण दिये जा रहे हैं । उर्वरकों की खरीद तथा उनके वितरण के लिये उत्पादकों को भी ऋण दिये जा रहे हैं ।

- (५) तकनीकी मार्गदर्शन : राज्यों में कपास के विकास से सम्बन्धित योजनाओं के लिये तीसरी योजना के अन्तर्गत पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध कर दिया गया है ताकि कपास उत्पादकों को

कपास उत्पादन के उन्नत तरीकों के बारे में सलाह दी जा सके।

- (६) पंकेज प्रोग्राम : पंकेज प्रोग्राम के अन्तर्गत अतिरिक्त स्टाफ की नियुक्ति के लिये व्यवस्था की गई है। ऐसे अतिरिक्त स्टाफ पर होने वाले खर्च को केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें समान रूप से बाटेंगी।

श्री रा० स० तिवारी : क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि देश में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये हर प्रान्त के जिलों को जो मदद दी जाने वाली है, वह रूपों में दी जायेगी या मशीनों, ट्रेक्टरों आदि के रूप में उनको मदद दी जायगी ?

डा० राम सुभग सिंह : मशीनों और कृषि औजारों के लिए २५ प्रतिशत सबसिडी दी जाती है। पेंस्टीसाइड्स, इंसेक्टीसाइड्स, दवाओं के लिये भी ५० प्रतिशत सबसिडी दी जाती है जिसका कि २५ प्रतिशत भाग केन्द्रीय सरकार वहन करती है।

श्री रा० स० तिवारी : क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सहायता प्रान्तों के मंत्रियों या प्रान्तीय सरकारों से पूछ कर दी जायगी या यहां से उसका सीधा सम्बन्ध होगा ?

डा० राम सुभग सिंह : सारी सहायता राज्य सरकारों की राय से और उनकी मार्फत दी जाती है।

**Shri P. Venkatasubbaiah:** In the statement laid on the Table of the House, various measures taken to step up food production in the different States had been given. However, no mention has been made regarding credit facilities to be given to the cultivators to reclaim land and intensify food production. I want to know whether there are any arrangements to give credit facilities to the farmers.

**Dr. Ram Subhag Singh:** Credit is one of the most important factors for improving agricultural production and a sum of Rs. 240 crores was advanced as agricultural credit. That comes under the Ministry of Co-operation. That sum was advanced last year. About Rs. 40 crores was distributed as taccavi loan by the State Governments. As that item comes under the Ministry of Co-operation, it has not been mentioned here.

**Shri Vidya Charan Shukla:** It has been said that as an incentive for better production of paddy, reasonable purchase prices are being fixed in different regions by the Government. May I know whether these prices are fixed by notification well before the paddy crop comes to the market or it is left to the regional directors to fix the price?

**Dr. Ram Subhag Singh:** It was announced about two months ago. In determining such things in future, we shall keep the observations of the hon. Member in mind.

**Shri Thirumala Rao:** Have the Government considered the desirability of putting food production and agricultural credit under one Ministry?

**Dr. Ram Subhag Singh:** That is a suggestion.

**Shri Inder J. Malhotra:** In the statement under every item it is said that the village level workers and block staff will be strengthened. I want to know whether this block staff will be working under the Ministry of Food and Agriculture or the Ministry of Community Development.

**Dr. Ram Subhag Singh:** They are working as they have been working before. The Ministry of Food and Agriculture and the Ministry of Community Development and Co-operation are both working in full co-operation and there is no difficulty in getting things done.

**Shri D. C. Sharma:** In the statement there is one word occurring constantly: 'subsidy'; subsidy is going

to be given for everything. May I know what arrangements are going to be made for the distribution of fertilisers, agricultural implements, pesticides and so on? What is the good of giving subsidy if these things are not increasingly made available?

**Dr. Ram Subhag Singh:** The quantity of nitrogenous fertiliser is increasing every day. This year we distributed about 4.9 lakh tons nitrogenous fertilisers. Wherever there is any disease noticeable, particularly if it happens in cash crop areas, we are sending our aerial unit and other units and we do spraying work. In every package district one workshop has been established for producing agricultural implements through blocks also we have been distributing improved agricultural implements in certain areas with a view to see that the growers take full advantage of this subsidy.

**Shri P. B. Chakraverti:** What are the criteria which have been determined for fixing particular areas for this increased production?

**Dr. Ram Subhag Singh:** In consultation with the State Governments these districts are selected, and the chief criteria particularly for paddy are that there should be irrigation facilities existing in that area. For bajra, jowar and pulses, the criteria are that they should be the chief bajra, jowar or pulses growing areas.

**श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** योजना आयोग की इस राष्ट्रीय विकास परिषद् ने पिछली दो पंचवर्षीय योजनाओं में निर्धारित लक्ष्य तक कृषि उत्पादन न पहुंचने के संबंध में भी क्या कोई असन्तोष व्यक्त किया है, यदि हां, तो उसके क्या कारण बतलाये गये हैं ?

**डा० राम सुभग सिंह :** अब असल में हम लोगों को तो कोई खास इस रूप में लिख कर दिया नहीं है कि असन्तोष है। अब असन्तोष के लिये अगर कारण कोई यह कहें कि जो ४ मिलियन एकड़ सिंचाई का साधन बनाया गया

था उस का उपयोग नहीं हो रहा है तो उस के लिये खाद्य और कृषि मंत्रालय कहां तक जवाबदेह है यह खुद माननीय सदस्य समझ सकते हैं।

**Shri Indrajit Gupta:** In the statement which has been given I find it stated that a reasonable purchase price for paddy and rice has been fixed in different areas. May I know whether this price is being statutorily fixed? What is the basis on which it is being fixed? If it is not being statutorily fixed, how do the Government propose to enforce it?

**The Minister of Food and Agriculture (Shri S. K. Patil):** The Government propose to enforce it as they have been enforcing it in the matter of wheat, etc., saying that this is the minimum price. Of course, we do not expect that the price should fall so low that the farmers should come to the minimum. But supposing that they reach the minimum, the Government enters the market and buys the stock so that the farmer should not suffer.

#### Wagon Shortage

\*11. **Dr. L. M. Singhvi:** Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) the position to date in respect of wagon shortage; and

(b) what steps have of late been taken to ensure a more satisfactory wagon-user position?

**The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Shahnawaz Khan):** (a) and (b). A statement is laid on the Table of the House.

#### STATEMENT

(a) There was a shortage of about 12,100 B.G. and 4,600 M.G. wagons against the Plan provision at the end of November, 1962.

(b) The following measures continue to be taken to increase wagon